



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2010/माघ 19, 1931

No. 246]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2010/MAGHA 19, 1931

बाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(बाणिज्य, विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2010

सं. 28/2009-2014

विषय : मेगा पावर प्रॉजेक्ट के संबंध में विदेश व्यापार नीति  
के अध्याय 8 में संशोधन।

का.आ. 288(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के  
पैराग्राफ 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन)  
अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  
केन्द्र सरकार, एतद्वारा विदेश व्यापार नीति (2009-2014), में  
निम्नलिखित संशोधन करती है :—

निम्नलिखित वाक्य को पैराग्राफ 8.4.4(iv) को प्रथम पंक्ति  
के अंत में जोड़ा जाएगा :—

“तथापि, मेगा पावर प्रॉजेक्ट के संबंध में, आई सी बी अनिवार्य  
नहीं होगा, यदि विद्युत की आवश्यक मात्रा को प्रशुल्क  
आधारित प्रतियोगी बोली के जरिए समझौते द्वारा प्राप्त किया  
गया हो या प्रॉजेक्ट को प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली द्वारा  
दिया गया हो।”  
इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/92/180/162/ए एम 08/पी सी-6]

आर. एस. गुजराल, विदेश व्यापार महानिदेशक  
एवं पदेन विशेष सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2010

No. 28/2009-2014

**Subject : Amendment in Chapter 8 of FTP regarding  
Mega Power Project.**

**S.O. 288(E).**—In exercise of powers conferred by  
Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation)  
Act, 1992 read with paragraph 1.3 of the Foreign Trade  
Policy (FTP), 2009-2014, the Central Government hereby  
makes the following amendments in FTP, 2009-2014.

Following sentence shall be added at the end of the  
first line of Paragraph 8.4.4 (iv):

“However, in regard to mega power projects, the  
requirement of ICB would not be mandatory, if the  
requisite quantum of power has been tied up through  
tariff based competitive bidding or if the project has  
been awarded through tariff based competitive  
bidding.”

This issues in public interest.

[F. No. 01/92/180/162/AM 08/PC-VI]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade  
& ex-officio Spl. Secy.